



The Uttar Pradesh Nagar Yojna or Vikas (Sanshodhan) Adhiniyam, 1978

Act 14 of 1978

Keyword(s):

High Court, Judge, Abolition of Letters Patent Appeals in Certain other Cases, Jurisdiction

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

187341

15/78-14H

cab. 2

विधान सभा

(राजकीय प्रशासन)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978*

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 14, 1978)

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 10 अप्रैल, 1978 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 17 अप्रैल, 1978 ई० की बैठक में स्वीकृत किया।]

(‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग 1-खंड (क) में दिनांक 27 अप्रैल, 1978 ई० को प्रकाशित हुआ।)

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

PRICE 15 PAIS

भारत गणराज्य के उन्तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अधिनियम, 1978 कहा जायगा।

संक्षिप्त नाम

*उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 20 मार्च, 1978 ई० का सरकारी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट का भाग 3-खण्ड (क) देखिये।

उत्तर प्रदेश अधि-
नियम संख्या 30,
1974 द्वारा यथा
पुनः अधिनियमित
राष्ट्रपति अधि-
नियम संख्या 11,
1973 की धारा
59 का संशोधन

निरसन

2—उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा 59 में, उपधारा (14) में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1979" रख दिये जायेंगे।

3—(1) उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1977 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित, धारा 2 में निर्दिष्ट अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम 30 दिसम्बर, 1977 को प्रवृत्त हो गया था।

उत्तर
अध्यादेश
सं 0 2
1977